नवम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक निम्नानुसार था:—

(आंकड़े मिलियन मीटरी टन में)

	1.7.95 की स्थिति के अनुसार (अनन्तिम)	1.10.95 की स्थिति के अनुसार	1.11.95 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)
गेहूं	19.17	16.78	15.77
चावल	16.44	13.00	12.41
जोड़	35.61	29.78	28.18

(ग) और (घ) बफर स्टाक रखने संबंधी वर्तमान नीति के अनुसार उपर्युक्त स्टाक सरकार द्वारा रखे जाने वाले न्यूनतम बफर मानदण्डों से कहीं अधिक है। जिसका ब्योरा निम्नानुसार है:—

(आंकड़े मिलियन मीटरी टन में)

तारीख	गेहूं	चावल	जोड़
पहली अप्रैल	3.7	10.8	14.5
पहली जुलाई	13.1	9.2	22.3
पहली अक्तूबर	10.6	6.0	16.6
पहली जनवरी	7.7	7.7	15.4

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने में उपयोग करने के अलावा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अधिशेष स्टाक का जवाहर रोजगार योजना, पोषाहार कार्यक्रम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के होस्टलों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों द्वारा चलाई जा रही खाद्य विधायन यूनिटों, मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और इसकी फ्रेन्चाइज्ड यूनिटों तथा मिड-डे-मील स्कीम जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन उपयोग किया जाए। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम घरेलू खपत और निर्यात के प्रयोजन के लिए गेहूं और चावल की खुली बिक्री कर रहा है। खाद्यान्नों की चालू वसूली के लिए भण्डारण स्थान खाली करने और खाद्यान्नों के बफर स्टाक पर रख-रखाव लागत के प्रति खर्च को कम करने की आवश्यकता अधिशेष स्टाक में कमी लाने के मुख्य कारण हैं।

Proposal for auction Platforms for Bidi Tobacco in Andhra Pradesh

1399. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to set up auction platforms for tobacco in Andhra Pradesh by the Tobacco Board;

(b) if so, the proposed, location of such platforms; and

(c) whether this proposal would benefit a large number of farmers in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir. There is no proposal to set up new auction platforms for tobacco in Andhra Pradesh. However, during 1994-95, 19 auction platforms were operated in Andhra Pradesh by the Tobacco Board.

(b) and (c) Does not arise.

Request of Additional Quota of Wheat etc.

1400. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether request have been received from the State Governments for enhancement of their quota of wheat, rice, sugar etc.;

(b) if so, the details thereof;

(c) the action taken thereon; and

(d) the manner in which the demands of the States are to be met in 1996?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) During 1995, requests have been received from the State Governments/UT Administrations of Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra,